(e)Likely to be completed by the 1st week of January, 1994.

(f) About 13 M. Kgs.

(g) Depending on market situation, a view regarding marketing of excess crop will be taken by the Board only after completion of marketing of the authorised crop.

Cases Against Tobacco Traders

1295. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Tobacco Board registered cases against some tobacco traders for resorting to purchase to tobacco outside the auction platforms;

$b) if so, whether they sought permission from Government;

(c) whether any. cases are pending with Government for which Tobacco Board has sought permission to register cases ;

(d) if so, what are the details and since when they are pending; and

(e) the number of cases that have been finalised so far with details, year-wise for the last three years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) to (d) Yes, Sir. 17 cases had been referred to Government by the Tobacco Board vide their letter dated 19-11-1993. The cases are under examination.

(e) Government has accorded sanction for prosecution in six cases relating to 1992 Karnataka auctions.

Indian Ocean Economic Bloc

1296. SHRI N. E. BALARAM :
SHRI CHATURANAN MISHRA :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the South African Foreign Minister Mr. R. F. Botha has suggested an Indian Ocean economic bloc; and

(b) if, so the details of the proposal and Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Yes, Sir.

(b) South African Foreign Minister has proposed intensified economic cooperation amongst the litteral countries of the Indian Ocean including South Africa, Pakistan, The Gulf and East African states. The Govt, of India is examining the suggestion.

देश में निर्यात और आयात में वृद्धि

1297. श्रीमती सत्या बहिन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश के आयात/निर्यात में कितनी-कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त अवधि में कतिपय देशों के साथ प्रथम बार कोई वाणिज्यिक अनुबन्ध किया है और उन देशों के नाम क्या-क्या हैं तथा इन देशों के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के आयात-निर्यात व्यापार का ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार इस सम्बन्ध में की गई प्रगति से संतुष्ट है ; और

(ग) क्या अमरीका द्वारा धारा 301 के अन्तर्गत लगाये गये व्यापार प्रतिबन्धों की कोई समीक्षा की गई है और क्या भारतीय व्यापार पर इस धारा 301 का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; यदि हां, तो इसके वर्तमान प्रभाव क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य देशों के साथ किए गए आयात/निर्यात के आंकड़े नीचे सारणी

में दिए गए हैं :—

(करोड़ रु०)

वर्ष	आयात	प्रतिशत परिवर्तन	निर्यात	प्रतिशत परिवर्तन
1990-91	43193	22.0%	32553	17.6%
1991-92	47851	10.8%	44042	35.3%
1992-93	63375	32.4%	53688	21.9%

(ख) जी हां । सरकार ने निम्नलिखित देशों के साथ पहली बार वाणिज्यिक करार किए हैं :—

आइवरी कोस्ट, चीन, रूसी, परिसंघ, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, आर्मीनिया, लिथुआनिया, लातिवा, इस्तोनिया, मालदोवा, बेलारूस, उक्रेन, स्लोवेनिया, चेक गणराज्य और स्लोवाक गणराज्य । इन देशों के साथ आयात/निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कुछ मदें इस प्रकार हैं :—

निर्यात	आयात
प्रसाधन/शृंगार सामग्री आदि रबड़ के विनिर्मित उत्पाद, धातु उत्पाद, प्लास्टिक एवं लिनोलियम उत्पाद, परिवहन उपस्कर, मशीनरी एवं उपकरण, वस्त्र-निर्मित यार्न/फैब्रिक/मेड-अप्स ।	काजू गिरि, विद्युत मशीनरी, धात्विक अयस्क और धातु छीलन ।

सरकार प्रगति से सन्तुष्ट तो है किन्तु उसमें आत्मसन्तुष्टि का कोई भाव नहीं है ।

(ग) अमरीकी प्रशासन ने दिनांक 30 अप्रैल, 1993 को ब्राजील और थाइलैण्ड के साथ-साथ भारत को फिर से अपने व्यापार कानून के स्पेशियल 301 प्रावधान के अधीन तथाकथित कमजोर बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के कारण प्राथमिकता वाला देश घोषित किया है । भारत सरकार ने अमरीकी प्रशासन को यह बतला दिया है कि बौद्धिक सम्पदा के मुद्दों पर उरूग्वे दौर में वार्ताएं चल रही हैं और इन वार्ताओं में इस मुद्दे के समाधान के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था है । हालांकि अमरीकी प्रशासन के दण्डात्मक कार्यवाही के लिए भारत का नाम तो नहीं लिया है लेकिन बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के बारे में अमरीकी चिन्ता के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को मानीटर करने के लिए अमरीका ने एक अन्तः अभिकरण दल का गठन किया है ।

Import of Raw Sugar

1298. PROF. SAURIN BHATTACHARYA :

SHRI N. GIRI. PRASAD:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

fa) whether it is a fact that Government are allowing raw sugar to be imported for processing the same for exports;

(b) whether the cost of processing would not be beneficial for determination of -export price ; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (c) The Imports & Exports Policy provides duly free import of raw material, components etc. for the manufacture and export